E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

सहरिया जनजाति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर विकास योजनाओं का प्रभा (शिवपुरी जिले के विशेष संदर्भ में)

श्रीमती पूनम सोनी

शोधार्थी भूगोल, जीवाजी विश्वविद्यालय

डॉ. साधना तोमर

प्राध्यापक,समाज शास्त्र

शा. ब्ही. आर.जी.महाविद्यालय,मुरार

Paper Rcevied date

05/05/2025

Paper date Publishing Date

10/05/2025

DOI

ABSTRACT

मध्य प्रदेश जनजातीय प्रदेश के रुप में जाना जाता है। इसमें विभिन्न जनजातियां निवास करती है। इनमें बैगा, भारिया, कोल, भील, सहरिया आदि प्रमुख है। प्रस्तुत शोध क्षेत्र के जनजातीय आबादी में सहरिया जनजाति का प्रमुख स्थान है, हालांकि, उत्तर–पश्चिम मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में ही इनका निवास स्थान है। इस लेख का उद्देश्य सहरिया जनजाति के समाजिक, आर्थिक जीवन पर विकास योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन अनुभवजन्य और द्वितीयक दोनों तरह के आंकड़ों पर आधारित है। शिवपुरी जिले में सहरिया आबादी 11.27 प्रतिशत है। उनके निवास स्थान वन क्षेत्र, बंजर और पथरीली भूमि में स्थित हैं और वे अभी भी एक आदिम समाज हैं। भारत की स्वतंत्रता के लंबे समय बाद भी, सहरिया जनजाति के लोग आर्थिक रूप से अविकसित और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उनके विकास के लिये कई योजनाऐं चलाई जा रही है। जिनका जनजातीय जीवन पर क्या प्रभाव पडा, इसी का विश्लेशण शोध का उद्देश्य है।

मुख्य शब्द – सहरिया, आर्थिक जीवन, निवास स्थान, वन क्षेत्र, शिवपुरी जिला

IMPACT FACTOR 5.924

परिचय –

मध्य–प्रदेश राज्य के उत्तरी भू–भाग में अवस्थित ग्वालियर संभाग के अंतर्गत शिवपुरी एक प्रमुख जिला है, जो भोपाल से लगभग 313 किमी आगरा–मुम्बई मार्ग पर निचले बिन्ध्य पठार की सुरम्य पहाड़ियों के बीच 24°,50′ से 25°,55′ अक्षांश व 75°,45′ से 78°,30′ देशांतर रेखाओं पर दक्षिण में मालवा पठार के सीमांत व पूर्व में बुंदेलखण्ड के मध्य अवस्थित है।[1] यह समुद्रतल से 521.5 मीटर उंचाई पर स्थिति है। शिवपुरी जिले का पूर्वी भाग बुन्देलखण्ड अंचल को स्पर्श करता है। उत्तर में मुरैना ग्वालियर और दतिया एवं दक्षिण में गुना स्थित है। पश्चिम में मुरैना जिले का कुछ भाग तथा राजस्थान का नवगठित

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

बांरा जिला तथा दक्षिण में गुना एवं अशोक नगर जिला शिवपुरी जिले का भौगोलिक परिसीमन करते हैं। जिले का आकार मोटे तौर पर चतुर्भजाकार है हालांकि पोहरी तहसील का एक संकीर्ण भाग पश्चिम की ओर फैला हुआ है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी सीमा लगभग 132 कि.मी. है जवकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौडाई 118 कि.मी. है।[2]

जनजाति शब्द का अर्थ है **एक समाज या समाज का विभाजन जिसके सदस्यों की वंशावली, रीति–रिवाज, विश्वास और नेतृत्व समान हो।** दूसरी ओर जनजातियों को ऐसे लोगों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनके पास व्यवसाय, सामाजिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक दृष्टिकोण जैसी कोई चीज समान होती है। भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा नियुक्त लोकुर समिति ने अनुसूचित जनजातियों को आदिम लक्षणों, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच, भौगोलिक अलगाव और पिछड़ेपन का संकेतक माना है।

वन क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियाँ अपनी आजीविका के लिए ज़्यादातर वन उत्पादों और पशुपालन पर निर्भर रहती हैं। कई क्षेत्रों में, उन्हें खानाबदोश कहा जाता है, जो एक जंगल से दूसरे जंगल में जाते रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में अनुसूचित जनजातियों को उन समुदायों के रूप में संदर्भित किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं। इसी प्रकार भारतीय सरकार द्वारा उनके हितों की रक्षा करने के लिए सन 1956 में एक सूची बनाकर तैयार की गई है जिसे **शेड्यूल ट्राइब्स लिस्ट मोडिफिकेशन ऑर्डर 1956 कहते हैं**इस प्रकार आदेश 414 के अनुसार इन्हें मूल जनजाति और उप–जनजाति में विभक्त किया गया है। इस प्रकार आज भारत में 550 जनजातीय निवास करती हैं।[3]

सहरिया शव्द फारसी के **सेहर** शब्द से व्युत्पन्न माना जाता है जिसका अभिप्राय जंगल में निवास करने से है।[4] मध्यप्रदेश के साथ–साथ राजस्थान को भी सहरियाओं की निवास स्थली माना जाता है। यद्यपि मध्यप्रदेश के मुकाबले में यहाँ सहरिया कम मात्रा में है मुख्यतः राजस्थान के सर्वाधिक सहरिया लोग बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में ही निवास करते हैं। यह राज्य का एकमात्र आदिम जनजाति समूह है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य में 59810 सहरिया लोग थे, जो राजस्थान राज्य की कुल जनजाति जनसंख्या का 1.09 प्रतिशत है वर्तमान में बारां जिले के किशनगंज तहसील में 9625 एवं शाहबाद तहसील में 10300 सहरिया परिवार निवास करते हैं, जिनकी जनसंख्या क्रमशः 1,36,091 तथा 1,08,146 तथा कुल 2,44,237 है।[5]

सहरिया जनजाति आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ी हुई जनजाति कही जा सकती है। ये प्रारम्भ से ही बहुत गरीब हैं। इनकी गरीबी के दो प्रमुख कारण है–

1. सामंत और उच्च जातियों जैसे ब्राह्मण, किराड़ एवं बनिया इत्यादि द्वारा इनका शोषण।

2. सरकारी मशीनरी तंत्र द्वारा इस शोषण का समर्थन ।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व सहरियाओं के रोजगार के दो ही साधन थे–प्रथम कृषि तथा खेतीहर मजदूरी और दूसरा, जंगल से प्राप्त होने वाली उपज को संग्रहीत कर बेचना। इसके अलावा धनी, व्यापारी, जमींदार, राजा महाराजा इनसे अक्सर काम

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

करवाते रहते थे। इस तरह से इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती थी, अतः इनका आर्थिक जीवन अत्यंत सरल माना गया है, जो कि मुख्यत खेती, मजदूरी, या जंगली उपज संग्रह पर आधारित है। कभी–कभी ये शिकार एवं मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। इन लोगों के पास खेती की जमीन बहुत कम होती है और वो पूर्ण रूप से असिंचित होती है। इस जमीन पर वर्षा ऋतु में ये हल चलाकर ज्वार, मक्का, तिल, बाजरा, गेहूँ आदि की खेती करते हैं। इनके खेती के औजार हल, बखर, खुर्पा, गुदाली, हनिया, कुल्हाड़ी, बैलगाड़ी व औखर आदि हैं, ये सभी औजार पुराने किस्मों के हैं, नए किस्मों के औजारों का उपयोग इनके यहाँ नहीं होता है। स्त्री–पुरुष दोनों ही खेती का कार्य करते हैं। पुरुष हल चलाने, बीज डालने, खेती की तराई, फसल कटाई, दाने साफ करने का कार्य करते हैं। इनकी स्त्रियाँ हल नहीं चलातीं, शेष अन्य कार्यों में वे पुरुषों की मदद करती हैं तथा घरेलू कार्यों में वे घर की सफाई, भोजन बनाना, पानी भरना, बच्चे की देखभाल करना व पुशओं की देखरेख भी करती हैं। जबकि पुरुष घर बनाने व बाजार से सामान लाने के साथ पशुओं की देखभाल करते है।[6]

सहरिया लोगों के घर तीन तरफ अंग्रेजी के अक्षर के यू के आकार में बने होते हैं जिसे **सहरा** कहते हैं बीच में सहरिया लोगों के सभी घरों के लिए एक साझा आंगन होता है महिलाएं पीली मिट्टी चौक और गेरू का लेप बनाकर उसे दरवाजे की चौखट आंगन और रसोई पर लगाती हैं जैसे –जैसे आधुनिकीकरण का दौर आया है वे इस काम के लिए बाजार से रंग खरीदती है और उससे वे शुभ आकृतियां बनाती हैं। यह कार्य लगभग हर रोज किया जाता है और सिर्फ खास मौकों तक सीमित नहीं है उनकी पेंटिंग में बहुत ही सौंदर्यबोध है और वे इसे अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में भी दर्शाते हैं।

इसी प्रकार श्रंगार, और आभूषण स्त्री की प्रियता और अलंकारों के प्रति उनका रुझान आदि काल से ही रहा है, सहरिया स्त्रियों में श्रंगार गोदने के रुप में देखने को मिलता है जो उनकी परम्परा का अभिन्न अंग है। एक रासायनिक तत्व की उपस्थिति में त्वचा को रंजित करना ही गुदना अथवा गोदना है। इसके अतिरिक्त सहरिया जनजाति की महिला कपाल पर टीका (अर्धचंद्र और बीच में बिंदी) गोदना सात आठ साल की उम्र में गुदवाती हैं यह कार्य उनके माता–पिता के घर में समारोह पूर्वक किया जाता है फिर नाक पर चार दाता त्रिभुजाकार में बांये नथुने पर गुदवाये जाते हैं जिसका अर्थ चार कोठी अनाज है कानों के दोनों किनारों में मंदिर की कलश के आकार में सात दाना गुदना गुदवाया जाता है जैसे कनपटी दाना कहा जाता है कनपटी पर हरे–हरे सात दाने हरित वन प्रांतर का प्रतीक है। ठुड्डी पर एक गोल दाढ़ी दाना लगाया जाता है दाढ़ी दाना पूर्ण चंद्र का प्रतीक है जिससे शांति और सुंदर चेहरे पर सदैव शीतल चांदनी की तरह बिखरा रहे। गोदना गुदवाने करने की बहुत पुरानी पद्धति बालोर का रस और बबूल के कांटे हैं बालोर के रस में कांटे को डुबोकर त्वचा में रस को प्रवेश कराया जाता था।

आजकल सभी महिलाएं बाजारों में मेले पर्वों पर मशीन से गोदने गुदवाने में विश्वास करती है मशीन के गोदनाकर बनी बनाई काली अमिट केमल स्याही का प्रयोग करने लगे हैं जिसे ड्राइंग इंक के नाम से जाना जाता है।[7]

सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में तीन विशेष पिछड़ी जनजातियों के साथ सहरिया को विशेष पिछड़ी जनजाति में अधिसूचित किया गया है विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए राज्य स्तरीय प्राधिकरण अभिकरण का गठन किया गया है प्रत्येक प्राधिकरण में विशेष पिछड़ी जनजाति के अध्यक्ष तथा तीन अशासकीय सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान है।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

सहरिया जनजाति समूह के विकास के लिए योजना बनाना एवं उनका क्रियान्वयन करना तथा अनुसरण करने हेतु निम्न अभिकरण कार्यरत हैं, जिसका कार्य क्षेत्र 08 जिलों में है।[8]

कार्यक्षेत्र एवं अभिकरण मुख्यालय

सहरिया विकास प्राधिकरण

मुख्यालय	कार्यक्षेत्र
श्योपुरकलां	1.श्योपुरकलां 2.मुरैना, 3.भिंड,
शिवपुरी	शिवपुरी
गुना	गुना, अशोकनगर
ग्वालियर	ग्वालियर, दतिया

मध्यप्रदेश एवं भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह के लिए अनेक योजनायें चलाई जा रही है। ताकि इन जनजातियों को आर्थिक रुप से सम्बल प्रदान किया जा सके। ये योजनायें इस प्रकार है।

पोषण आहार योजना –

सरकार द्वारा पोषण आहार अनुदान योजना चलाई जा रही है इस योजना के तहत पीटीएस जनजातीय परिवारों की महिला मुखिया को ₹1500 प्रति माह की दर से पोषण आहार अनुदान राशि दी जा रही है इसके लिए सरकार ने वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट में 450 करोड रुपए आवंटित किए गये हैं।

क्र	नाम	जनसंख्या	गांव	विकासखंड	जिला	निवास क्षेत्र
1	बैगा	131425	1143	22	6	डिंडोरी उमरिया अनूपपुर बालाघाट बैहर
2	सहरिया	4017171	1159	26	8	ग्वालियर चंबल संभाग की समस्त जिले
3	भारिया	2012	12	1	1	पातालकोट जिला छिंदवाड़ा
	योग	550608	2314	49	15	

सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए पोषण आहार योजना चलाई गई है जिसके अंतर्गत शिवपुरी शिवपुरी जिले में आठ विकासखंडों कि 2442 आंगनबाड़ियों में शिवपुरी जिले की 51946 महिलाओं को पोषण आहार के द्वारा लाभान्वित किया गया है।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

पीएम पोषण योजना– इसमें मध्य प्रदेश में कुल 24 PVTG जिलों में निरंतर रूप से खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है इस खाद्यान्न में बच्चों के लिए पका हुआ गरम पोषक भोजन उपलब्ध कराया जाता है पिछले वर्ष 2023–24 में इन 24 PVTG जिले में कुल 56703.89 और वर्ष 2024– 25 में 30 सितंबर 2024 तक इन्हीं PVTG जिलों को कुल 26494.66 मेट्रिक टन खाद्यान्न जारी किया गया है अब तक कुल विशेष रूप से पिछड़े जनजाति की 1.81 लाख जनजातीय बहनों को पोषण आहार के लिए 18.6 करोड रुपए का आंवंटन किया गया है।[9]

आवास योजना– भारत सरकार की पीएम जनमन योजना देश की विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 13 नवंबर 2023 को शुरू किया गयी थी। जिसके अंतर्गत सहरिया जनजाति को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए **शिवपुरी** जिले में सहरिया जनजाति के लिए आवास बनाए गए, शिवपुरी जिले में वर्तमान में कुल 36620 सहरिया हितग्राहियों के लिए आवास स्वीकृत हुए थे जिसमें 7064 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। आवास पूर्णता में शिवपुरी जिला देश और प्रदेश में प्रथम स्थान पर है और वर्तमान में शिवपुरी जिले में 14 कॉलोनियां निरमाणाधीन है। इन कॉलोनियों में आवास के अतिरिक्त रोड पानी, बिजली, चौपाल, स्ट्रीट लाइट, समुदायिक भवन आदि की सुविधा भी दी जा रही है।[10]

पी.एम. जन धन योजना– यह भारत सरकार की योजना है जिसके अंतर्गत, पीएम जनधन योजना में 5,46,3,35 व्यक्तियों को जन धन बैंक खाता के अंतर्गत सभी को आर्थिक उपलब्धि दिलाना था पीएम जन धन बैंक खाता खोलने के लिए सरकार द्वारा 5 लाख 46335 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया था। पीएम जन धन योजना के लाभ वितरण के लिए 4,35,3,76 व्यक्तियों को पात्र पाया गया था। जिसके कियान्वयन में 93.31 प्रतिशत लक्ष्य की उपलब्धि प्राप्त हुई है इस प्रकार इस योजना के द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को सक्षम वनाने का प्रयास किया जा रहा है।[11]

मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय योजना – यह योजना विशेष पिछड़ी बैगा, भारिया, सहरिया जनजातियों के लिए चलाई गई है इस योजना के तहत इनको आर्थिक सहायता हेतु गाय और भैंस प्रदान की जा रही है। शिवपुरी जिले में इस योजना के तहत सहरिया आदिवासियों को भैंस बांटने का क्रम शुरू हो चुका है अभी तक 140 हितग्राहियों को चिन्हित किया जा गया है और इसमें से 98 आदिवासी परिवारों को भैंस एवं गाय दे दी गई है इनमें 90 लोगों को भैंस एवं आठ लोगों को गाय प्रदान की गई है मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय योजना के तहत 90 अंशदान सरकार दे रही है शेष 10 प्रतिशत हितग्राहियों को देना होता है मुख्यमंत्री दुधारू गाय योजना के तहत सभी पशुओं का बीमा भी कराया जाता है।[12]

निष्कर्ष – इस प्रकार हम देखते है कि राज्य सरकार एवं भारत सरकार शिवपुरी के सहरिया आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिये विभिन्न कल्याण कारी योजनायें चला रही है ताकि उन्हें आर्थिक रुप से सम्बल प्रदान किया जा सके। मध्यप्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024–25 में अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए 40,804 करोड़ रुपये का बजट पारित किया, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 3,856 करोड़ रुपये अधिक है। इस बजट में 23.4: की वृद्धि की गई है, जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों की शिक्षा, रोजगार, और समग्र विकास पर विशेष ध्यान देना है, इसी प्रकार प्रधानमंत्री जन–मन अभियान

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

के तहत राज्य सरकार विशेष पिछड़े जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) जैसे बैगा, भारिया, और सहरिया के विकास के लिए कार्य कर रही है। इन जनजातियों के क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों, आवास, और शिक्षा से जुड़ी कई योजनाओं पर काम हो रहा है। इस अभियान के तहत सरकार ने 1,607 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। जनजातीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए पीवीटीजी बटालियन का गठन किया जा रहा है। यह बटालियन बैगा, भारिया, और सहरिया जनजातियों के लिए अलग से बनाई जाएगी। इसके अलावा, सेना, पुलिस, और होमगार्ड में भर्ती के लिए इन युवाओं को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मध्यप्रदेश सरकार ने पीवीटीजी आहार अनुदान योजना के तहत जनजातीय परिवारों की महिला मुखियाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह पोषण आहार अनुदान देने का प्रावधान किया है। इस योजना के लिए 450 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। साथ ही, आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही जनजातीय विद्यार्थियों को जेईई, नीट, क्लेट और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए राज्य सरकार रानी दुर्गावती प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कर रही है। इस अकादमी के जरिए विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें। मध्यप्रदेश में नवंबर 2022 से लागू पेसा नियमों से 20 जिलों की 11,596 ग्राम पंचायतों में जनजातीय समुदायों को लाभ मिल रहा है। इन नियमों के तहत जनजातीय समुदाय अपनी संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप विकास योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकते हैं। शिक्षा से जुडे छात्र/छात्राओं के लिये वित्त वर्ष 2023–24 में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत जनजातीय विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। प्री–मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 17 लाख से अधिक विद्यार्थियों को 56 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई। इसके अलावा, पोस्ट–मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 356 करोड़ रुपये वितरित किए गए। विदेश में पढ़ाई करने वाले 10 जनजातीय विद्यार्थियों को 2.89 करोड़ रुपये की विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति भी दी गई। इसके अलावा, किराया प्रतिपूर्ति योजना के तहत 1.44 लाख विद्यार्थियों को 109 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। राज्य के प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आकांक्षा योजना के तहत जेईई, नीट और क्लेट की तैयारी कराई जा रही है। अब इस योजना का विस्तार करते हुए सभी जनजातीय ब्लॉकों में मुफ्त कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। वर्तमान में शिवपुरी जिले के सहरिया इन सभी योजनाओं से लाभान्वित भी हो रहे है। जिससे सहरिया जनजाति के जीवन स्तर में अप्रत्याशित सुधार देखे जा सकते है।

संदर्भ सूची

1. एन.पी.पाण्डेय, म.प्र. डिस्ट्रिक्ट गजेटियर शिवपुरी, 1999 पृ. 11
2. वही पूर्वोक्त
3. तिवारी शिवकुमार, मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल 2023 पृ.सं.–14
4. बसंत निरगुणे सहरिया, मध्यप्रदेश लोक आदिवासी कला परिषद भोपाल, 1988 पृ. 03
5. श्रीवास्तव रश्मि, सहरिया जनजाति साहित्य एवं संस्कृति, पंचशील प्रकाशन,जयपुर 2012 पृ. 20
6. गुप्ता मंजू, जनजातियों का सामाजिक आर्थिक उत्थान, 2017 पृ. 38
7. तिवारी शिवकुमार, मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल 2023 पृ.सं.–14

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

8. प्रशासनिक प्रतिवेदन जिला शिवपुरी,वर्ष 2022–23 पृष्ठ संख्या 3–4

9. जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त जानकारी के आधार पर

10. अमर उजाला

11- mpcg-ndtv-in

12- Indiatimes-com